न्यायमूर्ति, के. कन्नन

एक. तीन मुद्दों पर विचार करने का आग्रह किया गया:

(1) इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो मुद्दे सामने आए हैं, वे हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के कथित अनुपालन में प्रबंधन द्वारा श्रमिक को दिए गए मुआवजे के बाद श्रमिक को दिए गए रोजगार की छंटनी की वैधता, लेकिन चुनौती* को इस आधार पर अपर्याप्त माना गया कि वह एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में 'कर्मचारी' था, जो 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार दे रहा था और जो प्रासंगिक प्रावधान लागू था वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एन था। बाद की धारा के तहत अपेक्षित मुआवजे का भुगतान उसे नहीं किया गया था और इसलिए, समाप्ति को बुरा बताया गया था। कामगार की ओर से एक अन्य आधार पर आग्रह किया गया था कि उसके कुछ कनिष्ठ थे, जिन्हें सेवा में बनाए रखा गया था, जबकि उनके साथ इस आधार पर सेवामुक्ति के उपचार में भेदभाव किया गया था कि उन्हें अधिशेष प्रदान किया गया था और इसलिए, एक मामला था। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-जी और 25-एच का उल्लंघन। विवाद का अंतिम बिंदु, जो कामगार की ओर से आग्रह किया गया था, वह था जो इस न्यायालय के समक्ष पहली बार कहा गया था, अर्थात् कार्यवाही की मृत्यु के दौरान, उसी पद पर भर्ती के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें वह था नियोजित किया गया था और इसलिए, एक कर्मचारी को अधिशेष प्रदान किए जाने के कारण बर्खास्तगी का कारण अब उपलब्ध नहीं था और प्रबंधन को नई भर्ती के बजाय कामगार को फिर

से नियोजित करना था। कामगार की ओर से यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में विज्ञापन को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, लेकिन इस न्यायालय ने कर्मकार को उचित राहत के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने पुन: रोजगार के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए नागरिक विविध याचिका दायर की है, भले ही बहाली संभव न हो।

द्वितीय. श्रम न्यायालय के समक्ष विवाद:

(2) इस मामले का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। याचिकाकर्ता को कई अन्य लोगों के साथ 18 जुलाई, 1991 के आदेश द्वारा अगले दिन, अर्थात् 19 जुलाई, 1991 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इस बर्खास्तगी को 8 कामगारों ने चुनौती दी थी, जो इस आदेश से व्यथित थे। 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 14161 में समाप्ति। रिट याचिका की अनुमति दी गई थी और प्रतिवादी-प्रबंधन ने एलपी एंड टीएसएफओ को प्राथमिकता दी थी। इस माननीय न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष 1992 का 822। तर्क का पूरा ध्यान इस बात से संबंधित है कि क्या श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एन के लाभ के हकदार थे - और इसके परिणामस्वरूप क्या प्रतिवादी एक औद्योगिक प्रतिष्ठान था जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एल के तहत परिभाषित किया गया था और क्या अध्याय V-B के प्रावधान उन पर लागू थे। डिवीजन बेंच ने अपील की अनुमति देते हुए और एकल न्यायाधीश के 24 अगस्त, 1993 के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि श्रमिक की ओर से उठाए गए इस तर्क का कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं था कि यह एक औद्योगिक प्रतिष्ठान था। हालाँकि,

इसने पूरी तरह से प्रबंधन के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, जब उसने देखा कि बेंच इस निष्कर्ष की अंतिम रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी कि निगम को औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं कहा जाना चाहिए। यह देखा गया कि यह तथ्य का प्रश्न था जिसे पार्टियों को संबंधित तर्कों के समर्थन में सबूत पेश करने का अवसर दिए जाने के बाद उचित कार्यवाही पर निर्धारित किया जाना था। बेंच ने माना कि प्रभावी वैकल्पिक उपाय श्रम न्यायालय के समक्ष एक निर्णय के माध्यम से एक संदर्भ था और रिट याचिकाकर्ताओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई थी। व्यक्तिगत कामगारों के दावे बयानों के माध्यम से किए गए विभिन्न व्यक्तिगत संदर्भों के माध्यम से विवाद को श्रम न्यायालय में भेजा गया। जिस पुरस्कार पर आपत्ति जताई गई वह कामगार द्वारा किए गए दावे को खारिज करने वाले संदर्भों में से एक था। श्रम न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले के निपटारे के बाद श्रमिक ने कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं दिया था और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि प्रतिवादी-प्रबंधन कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान था जिसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय V-B के तहत प्रावधान है लागू होगा. इसमें पाया गया कि धारा 25-एफ के तहत कामगार को दिया गया मुआवजा कानून का पर्याप्त अनुपालन था और कामगार के पास श्रम न्यायालय के समक्ष कोई उपाय नहीं हो सकता था। श्रमिक की इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि धारा 25-जी और 25-एच का भी उल्लंघन हुआ है, श्रम न्यायालय ने माना कि अन्य श्रमिकों के मामले, जिनके बारे में कहा गया था कि वे कनिष्ठ थे, का निष्कर्ष नहीं निकाला गया था और वहाँ थे अभी भी लंबित। कथित तौर पर कनिष्ठ कामगार कहे जाने वाले सत्यवान का विशेष संदर्भ देते हुए, श्रम न्यायालय ने प्रबंधन के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि सत्यवान का मामला अभी भी लंबित है और दो अन्य व्यक्ति, जिनके बारे में कहा गया था कि वे कनिष्ठ हैं, अर्थात् सिंट। सत्या देवी

और श्रीमती. किरण बाला को अनुकंपा के आधार पर पूर्व-कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी, और इसलिए, वे श्रमिकों की एक अलग श्रेणी के थे और इसलिए, धारा 25-जी और 25-एच के तहत सिद्धांत लागू नहीं किए जा सकते थे। लागू।

3. **समान प्रबंधन के संबंध में किसी अन्य कर्मचारी का औद्योगिक निर्णय-संबंधी लेकिन बाध्यकारी नहीं:**

(3) दलीलों में सबसे आगे, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान-वकील ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि एक अन्य कामगार, जिसके पास उसी आदेश से कर्मचारियों के साथ छंटनी का आदेश आया था, ने विवाद खड़ा किया था। श्रम न्यायालय के समक्ष जहां श्रम न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर बहाली का निर्देश दिया था कि छंटनी औद्योगिक नियमों के खिलाफ थी। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया और **हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड बनाम निर्मल कुमार**[1] के मामले में न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई बहाली की दिशा में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और केवल बकाया वेतन से संबंधित मुद्दे को लेकर संशोधन किया गया। कर्मचारी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस निर्णय को प्रबंधन के आचरण को प्रदर्शित करने वाला बताया, जब उन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में स्थिति और धारा 25-एन की प्रयोज्यता से इनकार नहीं किया था, जो श्रमिक के पक्ष में पाया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, मामले में श्रमिक के दावों को विफल करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए तर्कों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह नहीं किया गया था और

[1] (2008)2 एस.सी.सी. 366

इसलिए, प्रतिवादी को एक अलग तर्क लेने से रोक दिया गया था। अकेले याचिकाकर्ता के मामले के संदर्भ में। विद्वान वकील ने एक अन्य कामगार अर्थात् रमेश कुमार पुत्र बाबू राम के संदर्भ में एक अन्य मामले पर भी भरोसा किया, जहां श्रम न्यायालय ने पहले ही यह विचार कर लिया था कि यह एक औद्योगिक प्रतिष्ठान था और धारा 25-एन के उल्लंघन में की गई समाप्ति खराब थी। उनके अनुसार, प्रबंधन ने श्रम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में श्रमिक को बहाल भी कर दिया था और याचिकाकर्ता को बहाली के अधिकार से वंचित करते हुए बचाव करना उचित नहीं था।

(4) निर्मल कुमार के संबंध में श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष केवल बकाया मजदूरी के दावे के संबंध में था जब न्यायालय ने माना था कि निगम के तहत चल रहा था हानि और तामझाम वापस काम करने वाले को वेतन नहीं दिया जाएगा। यह औद्योगिक प्रतिष्ठान था या नहीं, इस मुद्दे को उठाया ही नहीं गया था। एक अन्य श्रमिक, रमेश कुमार के उदाहरण पर मांगे गए संदर्भ में श्रम न्यायालय के निष्कर्ष को प्रबंधन द्वारा अंतिम मानने से इनकार कर दिया गया है और यह निर्णय कि प्रबंधन एक औद्योगिक प्रतिष्ठान था, याचिकाकर्ता के लिए कोई मूल्य नहीं हो सकता है। मुझे यह देखने में कोई कठिनाई नहीं है कि न तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिसने इस मुद्दे पर निर्णय नहीं दिया कि प्रबंधन औद्योगिक प्रतिष्ठान था या नहीं, न ही धारा 25-एन की प्रयोज्यता के संबंध में श्रम न्यायालय द्वारा एक अन्य मामले में कोई निर्णय दिया गया। उन आपत्तियों को उठाने में प्रबंधन के खिलाफ एक बाध्यकारी निर्णय का गठन कर सकता है जो अब मेरे सामने उठाई गई हैं और जिन्हें श्रम न्यायालय द्वारा स्वीकार्य पाया गया है। हालाँकि, उन निर्णयों का एक साक्ष्यात्मक मूल्य होता है जिसे उचित समय पर नहीं लिया जाएगा जब मुद्दे पर

उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। एलपीएए न 822 ऑफ़ 1992 में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पहले ही दिए गए निष्कर्ष के मद्देनजर योग्यता पर विचार प्रासंगिक हो जाता है। में कहा गया कि इस बात का कोई प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं था कि निगम एक औद्योगिक प्रतिष्ठान था और इसे केवल श्रम न्यायालय के समक्ष साबित करना आवश्यक था।

चतुर्थ. 'औद्योगिक प्रतिष्ठान' के लिए परीक्षण

(ए) 'कारखाना' का अर्थ

(5) अध्याय V-बी की प्रयोज्यता स्थापित करने के लिए, कामगार की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आग्रह किया कि धारा 25 एल के तहत परिभाषित 'औद्योगिक प्रतिष्ठान' में फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम) में परिभाषित एक 'कारखाना' भी शामिल है। उनके अनुसार, 'फ़ैक्टरी' की परिभाषा इतनी व्यापक थी कि प्रतिवादी निगम को ऐसा प्राप्त हुआ। स्थिति। इसलिए, फ़ैक्टरी अधिनियम के तहत परिभाषा को यहां पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी: -

"(एम) "फ़ैक्टरी" का अर्थ उसके परिसर सहित कोई भी परिसर है –

(i) जहां दस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भी हिस्से में बिजली की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है, या आमतौर पर इस तरह से की जाती है, या

(ii) जहां बीस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भी हिस्से में

बिजली की सहायता के बिना विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है, या आमतौर पर इस तरह से की जाती है, —

लेकिन इसमें खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के संचालन के अधीन एक खदान या संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित एक मोबाइल इकाई, रेलवे रनिंग शेड या एक होटल, रेस्तरां या खाने की जगह शामिल नहीं है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए श्रमिकों की संख्या की गणना करने के लिए एक दिन में विभिन्न समूहों और रिले के सभी श्रमिकों को ध्यान में रखा जाएगा;

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर यूनिट को किसी भी परिसर या उसके हिस्से में स्थापित करने मात्र से इसे फ़ैक्टरी नहीं माना जाएगा यदि ऐसे परिसर में कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं चल रही है या उसका भाग, (रेखांकित करते हुए)।

(बी) 'विनिर्माण प्रक्रिया' का व्यापक अर्थ

(6) धारा की प्रासंगिकता की जांच केवल इस संदर्भ में की जाएगी कि क्या निगम द्वारा की गई गतिविधि में 'विनिर्माण प्रक्रिया' शामिल है, जिसे फैक्ट्री अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत परिभाषित किया गया है और यह उपयोगी होगी उसी को यहाँ पुनरुत्पादित करने के लिए:-

"(के) "विनिर्माण प्रक्रिया" का अर्थ है–

(i) किसी वस्तु या पदार्थ को उसके उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान की दृष्टि से बनाना, बदलना,

मरम्मत करना, अलंकृत करना, परिष्करण, पैकिंग, तेल लगाना, धोना, सफाई करना, तोड़ना, ध्वस्त करना, या अन्यथा उपचार करना या अनुकूलित करना, या

(ii) तेल, पानी, सीवेज या कोई अन्य पदार्थ पंप करना; या

(iii) बिजली पैदा करना, बदलना या संचारित करना; या

(iv) मुद्रण के लिए रचना प्रकार, लेटर प्रेस द्वारा मुद्रण, लिथोग्राफी, फोटोग्राव्योर या अन्य समान प्रक्रिया या पुस्तक बाइंडिंग:

(v) जहाजों या जहाज़ों का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, मरम्मत, परिष्करण या उन्हें तोड़ना; या

(vi) किसी भी वस्तु को कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित करना या भंडारण करना।

(7) यह देखा जा सकता है कि विनिर्माण प्रक्रिया में बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान का उपयोग करने की दृष्टि से किसी वस्तु या पदार्थ का निर्माण शामिल है। कर्मचारी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि 18-7-1991 को जारी छंटनी नोटिस में विशेष रूप से निम्नलिखित शब्दों में निगम की गतिविधि की प्रकृति से निपटा गया है: -

> "निगम भूमि समतलीकरण, भूमि सुधार के व्यवसाय में लगा हुआ है। गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और जिप्सम और विभिन्न उर्वरकों, कीटनाशकों, कीटनाशक फार्म मशीनरी की बिक्री में नियमित और साथ ही तदर्थ/डीपीएल आधार

> पर विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या शामिल है। जिप्सम आम तौर पर डीलरों द्वारा बेचा जाता है जबकि अन्य व्यवसाय निगम के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। (जोर दिया गया)

श्रमिक के वकील के अनुसार, निगम ने गुणवत्तापूर्ण बीजों को शामिल करते हुए अपनी गतिविधि स्वीकार की है। यद्यपि विभिन्न उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के जिप्सम की बिक्री मात्र एक विनिर्माण प्रक्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में खेतों में गतिविधि शामिल होती है जो विनिर्माण प्रक्रिया के बिना नहीं की जा सकती है। विद्वान वकील **कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भाग सिंह**[2]में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों और 'पंपिंग ऑपरेशन' में व्यक्तियों पर इसकी प्रयोज्यता से संबंधित इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला देते हैं। निर्णय का संदर्भ महत्व रखता है जहां एक पूर्ण पीठ फैक्ट्री अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत दी गई परिभाषा 'विनिर्माण प्रक्रिया' के आलोक में गतिविधि का उल्लेख कर रही थी। पूर्ण पीठ ने पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन से संबंधित मामले में कहा था, "यह आवश्यक नहीं है कि व्यावसायिक रूप से अलग उत्पाद प्रक्रिया से बाहर आए।" पूर्ण पीठ ने कहा था, "'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा को बहुत संकीर्ण संरचना देना उचित नहीं होगा ताकि इसके आवेदन को केवल कार्यस्थल तक ही सीमित रखा जा सके। विनिर्माण प्रक्रिया में व्यावसायिक रूप से भिन्न वस्तु का उत्पादन किया जाता है।" अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप एक विस्तृत परिभाषा को अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, पूर्ण पीठ ने माना था कि अधिनियम का उद्देश्य कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक और

---

[2] '1988 (2) पीएलआर 1

व्यावसायिक खतरों से बचाना और उनके लिए रोजगार की अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करना था- पूर्ण पीठ ने स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, उचित कार्य घंटों और अन्य लाभों के प्रावधानों को सभी 'कार्य स्थानों' पर लागू करने का आदेश दिया था।

(सी) 'विनिर्माण प्रक्रियाओं' के उदाहरण

(8) कामगार की ओर से पेश विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें 'विनिर्माण प्रक्रिया' की व्यापक व्याख्याएं शामिल हैं, जिसमें कोल्ड स्टोरेज में वस्तुओं को संरक्षित करना और भंडारण करना शामिल है (**कुंभकोणम दूध आपूर्ति सहकारी समिति, इसके सचिव बनाम क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मद्रास**[3] ट्रैक्टर और हार्वेस्ट कंबाइन की मरम्मत कार्य (**पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया**[4] दूध की खरीद और बिक्री इसे भंडारण के लिए कूलर में संग्रहित करने के बाद (**वेल्लिपलायम सहकारी दुग्ध आपूर्ति सोसायटी बनाम क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम**[5] श्रमिकों के आवास में बीड़ी बनाना (**राजंगम, सचिव जिला बीड़ी श्रमिक संघ बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य**[6] सामग्रियों की पैकिंग (**ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन बनाम डेव गृह उद्योग**[7] थोक में उत्पाद प्राप्त करना और

---

[3] 2003(3)एलएलजे416

[4] 2006 (2) पीएलआर 267

[5] 2004 एलआईसी 2715

[6] एआईआर 1991 एससी 216

[7] 2001-1-एलएलजे 42

ऐसे थोक उत्पादों को अनपैक करने के बाद उन्हें ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार पैक करना (**पैरी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, द्वितीय अतिरिक्त श्रम न्यायालय, मद्रास और अन्य**[8] 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। किसी भी निर्णय का मौजूदा मुद्दे से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन वे सभी यह दर्शाते हैं कि विनिर्माण प्रक्रिया की ओर जाने वाली कोई भी छोटी गतिविधि विनिर्माण प्रक्रिया के अर्थ में आनी चाहिए।

(डी) बीजों के उत्पादन में मानवीय हस्तक्षेप शामिल है, जो एक 'विनिर्माण प्रक्रिया' है

(9) इस मामले में, प्रतिष्ठान की गतिविधियों में गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन शामिल है जिसके लिए एक विशेष प्रक्रिया के मानवीय प्रयास की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप नए बीज प्राप्त होंगे। एक निर्माण अपने आप में एक बदलाव का संकेत देता है, हालांकि हर बदलाव निर्माण नहीं हो सकता है लेकिन किसी वस्तु या पदार्थ का हर बदलाव श्रम और हेरफेर के उपचार का परिणाम है। 'निर्माण' की अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स**[9] में कहा कि परिवर्तन होना चाहिए; एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाला एक नया और अलग लेख सामने आना चाहिए। यद्यपि उपरोक्त निर्णय कर कानून के संदर्भ में 'निर्माण' के संदर्भ में है, लेकिन इसका निर्माण की अवधारणा को समझने पर असर पड़ता है। विनिर्माण

[8] 1998-1-एलयू 406

[9] एआईआर 1963 एससी 791

स्वयं एक या अधिक प्रक्रियाओं का अंतिम परिणाम है जिसके माध्यम से मूल वस्तुओं को पारित किया जाता है। एक प्रक्रिया एक गतिविधि है, संचालन द्वारा जो विनिर्माण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और एक गतिविधि विनिर्माण के मध्यवर्ती चरण में किया जाने वाला एक संचालन है, यह स्वयं वस्तु में कोई बदलाव नहीं ला सकती है। 'प्रक्रिया' शब्द का प्राकृतिक अर्थ कुछ सामग्रियों के उपचार का एक तरीका है (**सीसीई आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क** बनाम **राजस्थान राज्य वाणिज्यिक कार्य**[10] में पैराग्राफ 14 और 20 देखें)। गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन अचानक से नहीं होता है; यह धरती से उगता है। यदि यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के विकास की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो यह विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा में नहीं आ सकती है, लेकिन यदि कोई मानवीय तत्व शामिल है जो गुणवत्तापूर्ण बीज पैदा करता है, तो यह समझ से बाहर है कि बीज 'विनिर्माण प्रक्रिया' के बिना आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि 1992 के एलपीए नंबर 822 में डिवीजन बेंच द्वारा तथ्य की नई जांच के निर्देश के बाद भी, कामगार ने खुद को कोई अतिरिक्त सबूत देने का अवसर नहीं दिया। गतिविधि की प्रकृति, लेकिन फिर भी वह गतिविधियों की प्रकृति की स्वीकृति पर भरोसा कर रहा था, जिसमें प्रबंधन छंटनी के आदेश के संदर्भ में लगा हुआ था, जब वह अभिव्यक्ति 'विनिर्माण प्रक्रिया' की एक महंगी व्याख्या के लिए प्रचार कर रहा था, जिसके संदर्भ में जो स्वीकारोक्ति की गई है, मुझे नहीं लगता कि यह मुझे किसी नए सबूत की तलाश करने के लिए मजबूर करेगी। पार्टी और प्रबंधन को बाध्य करने

[10] 1991 (4) एससीसी 473

के लिए निश्चित रूप से सबसे अच्छे सबूत उपलब्ध हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी गतिविधियों में गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन शामिल नहीं है। मेरे विचार से, यह स्वयं इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-लो में उल्लिखित 'औद्योगिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा के भीतर लाने के लिए पर्याप्त है।

(ई) प्रधान कार्यालय की निर्माण गतिविधि में सहायता की गतिविधि करना है -इसलिए, औद्योगिक प्रतिष्ठान का हिस्सा

(10) कामगार को वैसे भी एक और बाधा को पार करना था, अर्थात, अध्याय V-बी का आवेदन केवल उस प्रतिष्ठान के मामले में उत्पन्न होगा जिसमें कार्य दिवस के लिए औसतन 100 से कम कामगार नियोजित नहीं थे। लिखित बयान में प्रबंधन का तर्क यह था कि कर्मचारी मुख्य कार्यालय में कार्यरत था जहां 50 या 60 से अधिक व्यक्ति काम नहीं कर रहे थे और इसलिए, निगम के मुख्य कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों को एक विशिष्ट औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम करने वाला माना जाना चाहिए। और इसलिए, अध्याय V-B के प्रावधान आकर्षित नहीं होंगे। पुनः धारा 2(केए) के अंतर्गत निहित 'औद्योगिक प्रतिष्ठान या स्थापना' की परिभाषा इस प्रकार है:-

"(का) 'औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम' का अर्थ है और स्थापना या उपक्रम जिसमें कोई उद्योग चलाया जाता है:

बशर्ते कि जहां किसी प्रतिष्ठान या उपक्रम में कई गतिविधियां की जाती हैं और ऐसी गतिविधियों में से केवल एक या कुछ ही उद्योग या उद्योग हैं, तो, -

(ए) यदि ऐसे प्रतिष्ठान या उपक्रम की कोई इकाई, जो एक उद्योग होने के नाते कोई गतिविधि कर रही है, ऐसे प्रतिष्ठान या उपक्रम की अन्य इकाई या इकाइयों से अलग है, तो ऐसी

इकाई को एक अलग औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम माना जाएगा;

(बी) यदि प्रमुख गतिविधि या प्रत्येक प्रमुख ऐसे प्रतिष्ठान या उपक्रम या उसकी किसी इकाई में की जाने वाली गतिविधियाँ एक उद्योग है और ऐसी स्थापना या उपक्रम या उसकी इकाई में की जाने वाली अन्य गतिविधि या प्रत्येक अन्य गतिविधियाँ, चलने के उद्देश्य से अलग नहीं की जाती हैं और हैं, या ऐसी प्रमुख गतिविधि या गतिविधियों को चलाने में सहायता करने पर, संपूर्ण प्रतिष्ठान या उपक्रम या, जैसा भी मामला हो, उसकी इकाई को एक औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम माना जाएगा। "

यदि किसी प्रतिष्ठान में कई गतिविधियाँ चलती हैं और उद्योग में केवल एक या कुछ गतिविधियाँ चलती हैं, तो कोई भी इकाई जो अन्य इकाई से अलग हो जाती है, उसे एक अलग औद्योगिक प्रतिष्ठान माना जाएगा। खंड (बी) में परिभाषा में कहा गया है कि यदि प्रमुख गतिविधि एक उद्योग की है और अन्य गतिविधि अलग नहीं की जा सकती है और ऐसी प्रमुख गतिविधि को चलाने में सहायता करने के उद्देश्य से है, तो संपूर्ण प्रतिष्ठान या उपक्रम एक औद्योगिक प्रतिष्ठान माना जाएगा। किसी संगठन के लिए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रधान कार्यालय वास्तव में मस्तिष्क की प्रकृति है। वह खेत या धरती जहां बीज तैयार किए गए थे वह हृदय, पेट और पैर हो सकते हैं और प्रधान कार्यालय मस्तिष्क का पदार्थ है जो इसकी गतिविधियों को संचालित करता है। प्रधान कार्यालय का अस्तित्व गतिविधि को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से चलाने या चलाने में सहायता करने के उद्देश्य से है। यद्यपि किसी प्रधान कार्यालय को पूरी

तरह से एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मानना संभव हो सकता था यदि क्षेत्र में क्या होता है और प्रधान कार्यालय में इसे कैसे संभाला जाता है, इसके बीच कोई संबंध नहीं होता, विभिन्न स्थानों पर कार्मिक कैसे काम करते हैं, इस पर एक व्यापक नज़र एक ही संस्था के कामकाज की जिम्मेदारियां यह दिखाएंगी कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता। स्वीकृत मामला यह है कि निगम ने स्वयं 500-600 से अधिक पुरुषों और महिलाओं को रोजगार दिया है और मुख्य कार्यालय में काम करने वालों को भी केवल उसी प्रतिष्ठान के हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए जो गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में लगा हुआ है।

पांचवां. धारा 25एन के अनुरूप न होने वाला छंटनी नोटिस अमान्य है

(11) यदि निगम की गतिविधियों को विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा में शामिल किया गया है, जिस पर अध्याय पांचवां-बी की सुरक्षा लागू होती है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के अनुपालन में जारी किया गया छंटनी नोटिस का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। प्रतिष्ठान का तर्क है कि छंटनी नोटिस का अनुपालन किया गया था। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम करने वाले जिस कर्मचारी की छंटनी की जानी है, उसे धारा 25-एन के तहत नोटिस दिया जाएगा, जिसमें छंटनी के कारणों को दर्शाते हुए लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देने का प्रावधान है। माना कि ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया था और कामगार ऐसे नोटिस का हकदार था। यह इस संदर्भ में है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में अपनी स्थिति से इनकार न करने का प्रबंधन का आचरण महत्वपूर्ण हो जाता है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक अन्य श्रमिक निर्मल कुमार के मामले का फैसला कर रहा था, जिसे धारा 25-एन के तहत नोटिस का

हकदार पाया गया और लाभ उठाया गया। कामगार को केवल रुपये तक सीमित बकाया वेतन के साथ बहाली का अधिकार। एक ही संगठन में एक ही श्रेणी के अन्य श्रमिकों के साथ एक ही गतिविधि में लगे श्रमिकों के साथ बर्खास्तगी के संबंध में अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जो हंस के लिए अच्छा है वह गैंडर के लिए भी अच्छा है। चीजों की उपयुक्तता और उपचार की एकरूपता में जो बात निर्मल कुमार पर लागू होगी, वही इस मामले में काम करने वाले पर भी लागू होगी।

छठा. विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत कनिष्ठ कर्मियों को बनाए रखना-प्रबंधन पर सबूत का बोझ, छुट्टी नहीं दी गई

(12) कर्मचारी ने धारा 25-जी और 25-एच के उल्लंघन की भी शिकायत की थी और तर्क दिया था कि जिन व्यक्तियों को बाद में नियुक्त किया गया था, उन्हें बरकरार रखा गया था और यहां तक कि नियमित भी किया गया था। प्रबंधन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ऐसे तीन मामले थे, जो कामगार से कनिष्ठ थे, जिन्हें काम पर रखा गया था। औचित्य यह था कि उनमें से एक सत्यवान था। प्रबंधन का तर्क था कि सत्यवान के संबंध में मामला लंबित है और उसकी छंटनी भी हो चुकी है। जहां तक दो अन्य व्यक्तियों का संबंध है, उन्हें एक अलग श्रेणी के व्यक्तियों के अंतर्गत माना गया था जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति योजना के आधार पर रोजगार दिया जाना था। कामगार की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 'अंतिम आओ पहले जाओ' और 'पहले आओ अंतिम जाओ' की धारा 25-जी और एच के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धांत की वैधानिक आवश्यकता

में कोई अपवाद नहीं है और अनुकंपा नियुक्ति योजना की प्रयोज्यता स्वयं औद्योगिक विवाद अधिनियम की योजना से अछूता नहीं है। हालाँकि मैं इस तरह के तर्क को अस्वीकार करता हूँ कि धारा 25-जी या 25-एच किसी भी अपवाद को स्वीकार नहीं करता है, मैं मानता हूँ कि अपवाद को हमेशा उस व्यक्ति द्वारा साबित करना होगा जो अपवाद स्थापित करता है। प्रबंधन के लिए यह साबित करना पूरी तरह से स्वीकार्य होगा कि उन व्यक्तियों की श्रेणी के बीच रोजगार की एक विशेष योजना मौजूद थी, जिन्हें अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना था। योजना को सबसे पहले सिद्ध करना होगा। बचाव में दिया गया बयान अपने आप में सबूत की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं करता है। सेवा न्यायशास्त्र में भी, अनुकंपा नियुक्ति को हमेशा संविधान के अनुच्छेद 14 के अपवाद के रूप में देखा जाता है और न्यायालयों ने हमेशा माना है कि क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के हितकारी सिद्धांत का अपवाद है, इसलिए इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए। योजना के अलावा अन्यत्र रोजगार नहीं मिल सकता। यदि यह स्वीकार किया जाता है कि दो अन्य व्यक्ति थे, जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, जिन्हें अनुकंपा योजना पर नियुक्त किया जाना था, तो यह उक्त योजना को साबित करने के लिए प्रबंधन पर व्यवहार करता है और स्पष्ट करता है कि दो कर्मचारी, जिन्हें वरीयता में नियुक्त किया गया था उस कर्मकार को, जो निश्चित रूप से वरिष्ठ था, अनुकंपा आधार पर ऐसी नियुक्ति पर विचार करने की परिस्थितियाँ बताईं। इस मामले में मुझे लगता है कि कोई दस्तावेज़ दाखिल नहीं किया गया था। अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों की स्वयं जांच नहीं की गई है, ऐसी नियुक्ति के लिए जिन कारकों पर विचार किया गया, वे भी न्यायालय के समक्ष नहीं हैं। इसलिए, मुझे

लगता है कि जिस प्रबंधन के कंधे पर यह दिखाने का भार था कि कनिष्ठ कर्मचारी याचिकाकर्ता के दावों पर विचार करने के हकदार थे, वह इस तरह के अनुकूल विचार के लिए औचित्य स्थापित करने में विफल रहा है। कामगार के बहाली के दावे में यह नहीं दर्शाया गया कि उसे उचित कारणों से विस्थापित किया गया है।

छठी. इसके बाद की घटना पर विचार नहीं किया गया

(13) कर्मचारी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उसी पद के लिए नया विज्ञापन जारी करने में प्रबंधन के आचरण की बाद की घटना पर भी तर्क दिया। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई निर्णय लेना आवश्यक है, मेरे द्वारा दिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि प्रबंधन द्वारा की गई छंटनी कानून की नजर में वैध नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में कर्मी का बहाली का दावा सफल होना तय है। श्रम न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है और कामगार बहाली का हकदार है, यदि वह पहले से ही सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंचा है। मुक़दमा दो दशकों से अधिक समय से चल रहा है और जितनी अवधि तक उसने काम नहीं किया है, वह उसी तरह पूर्ण बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा, जिस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य कामगार के मामले को निपटाया था। श्रमिक पिछली मजदूरी का केवल 25% ही पाने का हकदार होगा।

सातवीं. निष्कर्ष

(14) रिट याचिका में कामगार को सेवा की निरंतरता और ऊपर बताए गए पिछले वेतन के साथ बहाली की अनुमति दी गई है, जिसमें कामगार के पक्ष में 10,000 रुपये का मूल्यांकन किया गया है।

आर . एन . आर .